

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल कोठारी

अपीलान्त  
जोगा पुत्र उदा जाति कुम्हार  
साकिन दामण तहसील बागोडा  
जिला जालोर

बनाम

आई.ए.एस  
रेस्पोडेन्ट्स

1. करणा पुत्र नेथी  
2. रूपा पुत्र राईगा जातियान चौधरी  
साकिन दामण तहसील बागोडा  
जिला जालोर  
3. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी  
तहसीलदार बागोडा जिला जालोर  
47/2016

प्रकरण संख्या अपील

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री त्रिलोकचंद मेहता/श्री फरमानअली अभिभाषक अपीलान्त
- 2-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2
- 3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 08.01.2018

1. अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम दामण के नामान्तरकरण संख्या 687 पर पारित किया गया है।
2. अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
3. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलाधीन म्यूटेशन सहायक कलेक्टर बागोडा के द्वारा विधि विरुद्ध राजस्व केम्प में पारित निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को फायदा देने के लिये स्वीकृत किया गया है। जो प्रथमदृष्टया ही गलत होने से निरस्त करने योग्य है। मौजा दामण में पुराने खसरा नंबर 61 का मूल रकबा 14 बीघा होना स्वीकृत तथ्य है तथा इस खसरा नंबर की आराजी में पीरिया, वैला, पिसरान खेदा का 1/2 हिस्सा व जोगा पुत्र उदा का 1/2 हिस्सा है। खसरा नंबर 61 सहित पक्षकारों के बीच बंटवाडा हेतु अपीलांत जोगा ने एक वाद सहायक कलेक्टर भीनमाल में पेश किया जो राजस्व वाद मुकदमा नंबर 76/79 जोगा पुत्र पीरिया के नाम से दर्ज हुआ तथा जरिये राजीनामा यह वाद निर्णित होकर खसरा नंबर 61 की 7 बीघा भूमि पूर्व दिशा वाली जोगा पुत्र उदा के बंट में रखी व इसी प्रकार पीरिया व वेला के खसरा नंबर 61 की सात बीघा भूमि पश्चिम दिशा वाली बंट में रखी। खसरा नंबर 61 के अलावा भी अन्य आराजी का बंटवाडा हुआ था और इस प्रकार इस निर्णय के अनुसार पीरिया के हक में 3 बीघा 10 बिस्वा, इसी प्रकार वेला के हक में 3 बीघा 10 बिस्वा हिस्से में आती है। राजस्व वाद प्रकरण संख्या 76/79 की पालना में भूमिधारी के द्वारा तैयार किया गया रेकॉर्ड त्रुटिपूर्ण बना, हालांकि प्रकरण संख्या 76/79 के निर्णय के अनुसार जोगा अपीलांत की तमाम आराजी जरिये बंटवाडा अलग हो चुकी। जिसका कोई संबंध वेला व पीरिया की आराजी के साथ नहीं रहा। लेकिन भूमिधारी तहसीलदार बागोडा के द्वारा वाद संख्या 76/79 की पालना गलत कर वेला व पीरिया के हक में आई आराजी में 7 बीघा के स्थान पर 14 बीघा दर्ज की और जहां से विवाद शुरू हुआ। कालान्तर में सैटलमेंट के दौरान वेला व पीरिया के हक में आई आराजी खसरा नंबर के नये नंबर 90 दिये गये तथा जोगा के हक में राजस्व प्रकरण संख्या 76/79 के निर्णय के जरिये हक में आयी आराजी का नया खसरा नंबर 87 दिया गया है। जिसका भी कोई संबंध वेला व पीरिया की आराजी के साथ नहीं है। वेला व पीरिया पिसरान खेदा के गलत रेकॉर्ड के आधार पर पीरिया ने खसरा नंबर 61 का 7 बीघा आराजी का बेचान दस्तावेज रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 के हक में कर दिया जबकि पीरिया को 3 बीघा 10 बिस्वा से अधिक भूमि बेचने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि वाद संख्या 76/79 के निर्णय के अनुसार जो पीरिया व वेला के हक में दोनो को मिलाकर 7 बीघा ही भूमि प्राप्त हुई थी।

Sd-

भूमिधारी तहसीलदार के गलत रेकॉर्ड तैयार करने से रेस्पोंडेन्ट नंबर 1 व 2 ने एक वाद सहायक कलेक्टर बागोडा के न्यायालय में नये खसरा नंबर 87 में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया तथा वाद का जबाब दावा अपीलांत जोगा द्वारा प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर बागोडा को सही स्थिति से अवगत करवाया।

राजस्व केम्पो के दौरान सहायक कलेक्टर बागोडा ने राज्य सरकार की योजना के विपरित अपीलांत को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी राजीनामा के, बिना साक्ष्य हुये मनमाने तौर पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के वाद को डिक्री कर दिया। जो प्रथमदृष्टया ही न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित है तथा बिना साक्ष्य लिये वाद प्रमाणित कानून नहीं माना जा सकता है तथा वाद के निर्णय के दिन अपीलांत हाजिर भी नहीं था, न ही अपीलांत ने राजीनामा किया और बाला बाला सहायक कलेक्टर बागोडा ने मनमाने तौर पर वाद का निर्णय कर दिया तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 बिना किसी जांच के एवं बिना किसी पूर्व रेकॉर्ड की स्थिति का अवलोकन किये एवं वाद संख्या 76/79 का निर्णय प्रभावी होने के बावजूद भी अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया और इस प्रकार सहायक कलेक्टर बागोडा का निर्णय प्रभावहीन है। अपीलांत के हक में जरिये बंटवाडा मिली आराजी खसरा नंबर 87 में रेस्पोंडेन्ट नंबर 1 व 2 का कोई हक व हकूक नहीं है और न ही बेचान दस्तावेज में शामिल है। यहां तक कि वेला पुत्र खेदा के द्वारा भी पीरिया के साथ आराजी बेचान में शामिल नहीं था। जिससे वेला की आराजी का भी बेचान माना जाना न्यायसंगत नहीं है तथा वाद संख्या 76/79 के अनुसार पीरिया व वेला का 7 बीघा से अधिक भूमि पर कोई हक हकूक नहीं है। नये खसरा नंबर 87 पर अपीलांत काबिज है एवं पूर्व डिक्री संख्या 76/79 के पारित होने के पश्चात से लगातार अपीलांत वर्तमान खसरा नंबर 87 पर काबिज है। अपीलांत को अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 09.09.2016 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। जानकारी की दिनांक से अपीलांत की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 2 विद्वान अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2015 अनवान करणा वगैराह बनाम जोगा वगैराह में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 की पालना में भरा गया है। जो विधीवत है। उक्त दावे की कोई अपील भी नहीं की गई है। अतः अपीलांत की अपील अस्वीकार की जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश की पालना में भरा गया है। अपीलाधीन आदेश विधीवत है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वाद सुनवाई के अपीलांत की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा दावा संख्या 39/15 अनवान करना वल्द नैथी वगैराह बनाम जोगा वल्द उदा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2017 में यह आदेश पारित किया गया कि "तहसीलदार बागोडा को आदेश दिये जो हैं कि मौजा दामण के खसरा नंबर 87 रकबा 0.82 हेक्टर किस्म बारानी दायम के 1/2 हिस्से में वादी करना वल्द नैथी व रूपा वल्द राईगा का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करें।" तदनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बागोडा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/963 दिनांक 27.06.2016 की पालना में आदेशानुसार नामान्तरकरण दायर किया गया व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपीलांत की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)  
जिला कलेक्टर  
जालोर

निर्णय 08.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)  
जिला कलेक्टर  
जालोर